



## वैश्विक नविश केंद्र के रूप में भारत का उदय

यह संपादकीय 26/09/2024 को हदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित [“The world wants to Make in India”](#) पर आधारित है। यह लेख मेक इन इंडिया पहल द्वारा संचालित एवं स्टार्टअप इंडिया और PLI योजनाओं जैसी प्रतियोगिता नीतियों द्वारा समर्थित भारत के वैश्विक नविश केंद्र में परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। यह अपने “चार D” के माध्यम से भारत की अपील और खलौना निर्माण जैसे क्षेत्रों में सफलता को रेखांकित करता है, जिससे नरियात, रोजगार सृजन और वदेशी नविश में वृद्धि हुई है।

### प्रलिमिस के लिये:

[मेक इन इंडिया पहल](#), [स्टार्टअप इंडिया](#), [उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन](#), [आत्मनिर्भर भारत अभियान](#), [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन](#), [भारत औद्योगिक भूमि बैंक](#), [कवाड](#), [आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता पहल](#), [स्टार्टअप इंडिया पहल](#), [डजिटल अवसंरचना](#), [भूमि अर्जन](#), [पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013](#)

### मेन्स के लिये:

एक नविश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण में बाधा डालने वाली चुनौतियों, एक नविश गंतव्य के रूप में अपना आकर्षण बढ़ाने के लिये भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम।

आर्थिक रूप से नरिद्ध राष्ट्र से वैश्विक नविश अधिकांश में भारत के परिवर्तन का श्रेय [मेक इन इंडिया पहल](#) को दिया जा सकता है। इस प्रमुख कार्यक्रम ने [रोजगार सृजन को पुनर्जीवित किया है](#), [आर्थिक विकास उत्प्रेरित किया है](#) और [व्यवसायों](#), विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिये सशक्त बनाया है। इसने कई क्षेत्रों को घटिया उत्पादों के आयातकों से प्रीमियम वस्तुओं के निर्यातकों में परिवर्तित करने में सहायता की है, जिसमें खलौना निर्माण उद्योग एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने [निर्यात में 239% की वृद्धि देखी जबकि आयात आधा रह गया](#)।

मेक इन इंडिया की सफलता को [स्टार्टअप इंडिया](#), [उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन \(PLI\) योजनाओं](#) और [महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के नविश](#) जैसी अन्य प्रभावी नीतियों और पहलों द्वारा पूरति किया गया है। इन प्रयासों ने पर्याप्त वदेशी नविश को आकर्षित किया है, लाखों नौकरियों सृजित की हैं तथा भारत को उच्च तकनीक और उभरती प्रौद्योगिकियों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है। वैश्विक नविशकों के लिये देश की अपील इसके **“चार D”**: **नरिणायक नेतृत्व**, **बड़ी आबादी से मांग**, **जनसांख्यिकीय लाभांश** और **संपदनशील लोकतंत्र** द्वारा और भी बढ़ जाती है। परिणामतः, भारत वनिरिमाण और नवाचार के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, जिसका भविष्य उज्ज्वल है।

## भारत किस प्रकार एक आकर्षक नविश स्थल बनता जा रहा है?

- **सुदृढ़ आर्थिक विकास**: भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें **अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक कुल FDI प्रवाह 990.97 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है**।
  - IMF को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP में **6.7% वृद्धि होगी**, जिससे यह सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा।
  - [आत्मनिर्भर भारत अभियान](#) के तहत **270 बिलियन अमरीकी डॉलर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पेश किया गया**, जो देश की GDP के **10% के बराबर है**।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश**: भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी अनुमानित वृद्धि वर्ष 2011 में 121.1 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक 152.2 करोड़ हो जाएगी, जो इसे जनसांख्यिकीय लाभ का केंद्र बनाती है। जीवित कार्यबल और युवा प्रतियाओं के विशाल समूह के साथ **भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से सबसे युवा देशों में से एक बना रहेगा**।
  - यह युवा आबादी तेज़ी से तकनीक-प्रेमी हो रही है, अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या **900 मिलियन तक पहुँच जाएगी**, जिससे ई-कॉमर्स, डजिटल सेवाओं और तकनीक-सक्षम क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न होंगे।
- **अवसंरचना विकास**: भारत का अवसंरचना विकास तेज़ी से अग्रेषित हो रहा है, जिसमें [राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन \(NIP\) विकास का प्रमुख चालक है](#)।

- इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना और वित्त वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।
- 3,093.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 9,700 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो ऊर्जा (24%), सड़क (18%), शहरी (17%) और रेलवे (12%) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वित्तित हैं।
  - इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण इक्विटी निवेश से वैश्विक निवेश आकर्षित करने की भारत की क्षमता और सुदृढ़ होगी।
- **इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार:** भारत सरकार ने कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने के लिये कई सुधार कार्यान्वित किये हैं।
  - विश्व बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का श्रेणीकरण वर्ष 2014 में 142 से सुधरकर वर्ष 2019 में 63 हो गया है।
  - हाल की पहलों में 25,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त करना प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और माल एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत शामिल है।
  - GIS आधारित पोर्टल, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) औद्योगिक पार्कों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में संवर्द्धन होता है।
- **प्रतिस्पर्धी श्रम लागत:** भारत का वित्तित और वर्द्धति कार्यबल निवेशकों को महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करता है।
  - भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति है, जो विभिन्न कौशल स्तरों पर श्रमिकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। भारतीय श्रम लागत कई अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनी हुई है, विशेषकर वननिर्माण और सेवा क्षेत्रों में।
  - भारत में औसत वननिर्माण श्रम लागत चीन और कई दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है।
  - हाल के श्रम सुधारों का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यवसायों को अधिक समुत्थानशीलता प्रदान करना है, जिससे भारत संभवतः श्रम-प्रधान उद्योगों के लिये अधिक आकर्षक बन जाएगा।
- **वित्तित एवं वर्द्धति उपभोक्ता आधार:** भारत का वित्तित और वर्द्धति उपभोक्ता बाजार निवेशकों के लिये एक प्रमुख आकर्षण है:
  - भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.78% के बराबर है, जो एक वित्तित संभावित ग्राहक आधार प्रदान करती है।
  - मध्यम वर्ग की संख्या वर्ष 2020-21 में 432 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2030-31 में 715 मिलियन (47%) हो जाने की उम्मीद है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होगी।
- **सामरिक भू-राजनीतिक अवस्थिति:** भारत के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्त्व और हृदि-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रति संतुलन के रूप में इसकी स्थिति ने वैश्विक निवेशकों के लिये इसके आकर्षण को बढ़ा दिया है।
  - क्वाड (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) जैसे सामरिक समूहों में भारत की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों में इसका नेतृत्व इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
  - हाल के घटनाक्रमों, जैसे कि आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता पहल, ने चीन के विकल्प की तलाश कर रहे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिये इसकी अपील को और बढ़ा दिया है।
- **संवर्द्धति स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है।
  - 3 अक्टूबर 2023 तक, भारत में 111 यूनिफॉर्म हैं जिनका कुल मूल्य निर्धारण 349.67 बिलियन डॉलर है।
  - वर्ष 2016 में शुरू की गई सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल ने वित्तपोषण, कर लाभ और नियामक सहायता प्रदान करके इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - इस संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र ने महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया है, भारतीय स्टार्ट-अप ने वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धीताओं के बावजूद वर्ष 2022 में इक्विटी फंडिंग में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर संगृहीत किये हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा वर्द्धन:** नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने पर्याप्त निवेश अवसर उत्पन्न किये हैं।
  - देश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, जो वर्ष 2023 की शुरुआत में लगभग 170 गीगावाट था।
  - इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश को दलपटयुक्त किया है।
    - ऐसी पहल न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करती है, बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिये वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करती है।
- **डिजिटल अवसंरचना और फनितेक क्रांति:** भारत की डिजिटल अवसंरचना, विशेषकर इंडिया स्टैक ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है और नए निवेश अवसर उत्पन्न किये हैं।
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने प्रतिसेकंड 3729.1 लेनदेन संसाधित किये, जिससे वर्ष 2023 में प्लेटफॉर्म पर 117.6 बिलियन संव्यवहार संसाधित किये गए।
  - इस डिजिटल आधार ने फनितेक के विकास को उत्प्रेरित किया है, भारत का फनितेक बाजार वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - वैश्विक प्रौद्योगिकी दगिगज और उद्यम पूंजीपति भारत के बड़े, कम सेवा वाले बाजार और नवीन डिजिटल समाधानों की क्षमता को पहचानते हुए भारतीय फनितेक स्टार्टअप में तेजी से निवेश कर रहे हैं।

## निवेश गंतव्य के आकर्षण रूप में भारत के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ बाधा उत्पन्न करती हैं?

- **अवसंरचना अंतराल:** महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, भारत की अवसंरचना अभी भी वैश्विक मानकों से पीछे है, जिससे व्यवसायों की दक्षता प्रभावित हो रही है और लागत में वृद्धि हो रही है।
  - वर्ष 2023 में विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, जो सुधार की संभावना को प्रदर्शित करता है।

- अवसंरचना की कमी विशेष रूप से वदियुत् वतिरण, जलापूर्त और अंतमि छोर तक संयोजकता जैसे क्षेत्रों में गंभीर है, जिससे वनिरिमाण प्रतस्पर्द्धात्मकता प्रभावति हो रही है।
- **वनियामक जटलिता और नीति अनश्चितता:** भारत के वनियामक वातावरण में यदयपि सुधार हो रहा है, परंतु जटलि और कभी-कभी अप्रत्याशति बना हुआ है, जिससे संभावति नविशक हतोत्साहति हो रहे हैं।
  - हाल के उदाहरणों में **वोडाफोन और केयरन एनर्जी** जैसी कंपनियों के साथ पूरवव्यापी कर वविाद शामिल हैं, जो वर्षों की मुकदमेबाजी के बाद वर्ष 2021 में ही हल हो पाए।
  - **ई-कॉमर्स नियमों और डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं** में लगातार परविरतन ने भी तकनीकी कंपनियों के लयि अनश्चितता को उत्पन्न कयिा है।
- **श्रम बाज़ार की कठोरता:** भारत के नए 4 श्रम संहतिा जो वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पेश कयि गय थे, अभी तक कारयानवति नहीं हुए हैं। असंगठति क्षेत्र के श्रमकि देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक हसिसा है।
  - श्रम बाज़ार में कौशल का बेमेल होना एक और चतिा का वषिय है। वर्ष 2019 के एक रोजगार सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80% भारतीय इंजीनयिर ज्ञान अरथव्यवस्था में कसिी भी नौकरी के लयि उपयुक्त नहीं हैं और उनमें से केवल 2.5% के पास कृतरमि बुद्धमितता (AI) में तकनीकी कौशल है जिसकी उदयोग को आवश्यकता है।
- **बैंककि क्षेत्र की चुनौतयिाँ:** भारतीय बैंककि क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनकि क्षेत्र के बैंक, उच्च गैर-नषिपादति परसिंपतयिों (NPA) और पूजी पर्याप्तता के मुददों से जूझ रहे हैं, जिससे व्यवसायों को ऋण प्रवाह बाधति हो रहा है।
  - RBI की जून 2024 की वत्तितीय स्थरिता रपिरट के अनुसार, अनुसूचति वाणजियकि बैंकों की गैर-नषिपादति परसिंपतयिों (NPA) (हालॉक घट रही हैं) अभी भी 2.8% (सकल NPA) पर हैं।
  - हाल ही में वर्ष 2020 में यस बैंक के लगभग दवालियिा हो जाने से वत्तितीय प्रणाली की स्थरिता पर प्रश्न उठे हैं।
- **भूमि अरजन संबंधी चुनौतयिाँ:** भारत में बड़े पैमाने की औदयोगकि और अवसंरचना परयोजनाओं के लयि भूमि अधगिरहण एक महत्त्वपूरण बाधा बनी हुई है।
  - **भूमि अरजन, पुनरवासन और पुनरव्यवस्थापन में उचति प्रतकिर और पारदरशति अधकिार अधनियम 2013** ने भूमि स्वामयिों के अधकिारों की रक्षा करते हुए, इस प्रकरयिा को अधिक समय लेने वाली और महंगी बना दयिा है।
  - उदाहरण के लयि, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परयोजना को भूमि अरजन संबंधी समस्याओं के कारण क्काफी देरी का सामना करना पड़ा है।
  - कई राज्यों में डजिटिल भूमि अभलिखों का अभाव इस प्रकरयिा को और जटलि बना देता है, जिससे वविाद और परयोजना में वलिंब होता है।
- **बौद्धकि संपदा अधकिार (IPR) संबंधी चतिाएँ:** यदयपि भारत ने अपनी IPR व्यवस्था को सुदृढ बनाने में प्रगति की है, फरि भी अंतरराष्टरीय नविशकों, वशिषकर औषध और प्रौदयोगकि जैसे क्षेत्रों में, चतिाएँ बनी हुई हैं।
  - यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2023 अंतरराष्टरीय IP सूचकांक में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है।
  - देश के पेटेंट कानून, वशिषकर पेटेंट अधनियम की धारा 3(D), जो औषध क्षेत्र में पेटेंट के लयि उच्च मानदंड नरिधारति करती है, वविाद का वषिय रही है।
  - नकली वस्तुओं का प्रचलन, वर्ष 2022 की फकिी रपिरट के अनुसार भारत में नकली बाज़ार का आकार 2.6 ट्रिलियन रुपये (5 प्रमुख भारतीय उदयोगों में) होने का अनुमान है, जो IPR संरक्षण में चुनौतयिाँ को और अधिक रेखांकति करता है।
- **डजिटिल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा:** तीवर डजिटिलिकरण के बावजूद, भारत को अभी भी डजिटिल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा में चुनौतयिाँ का सामना करना पड़ रहा है, जो तकनीकी क्षेत्र में नविश आकरषति करने के लयि महत्त्वपूरण हैं।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतकिरयिा टीम (Cert-In)** ने वर्ष 2022 में 1,391,457 साइबर सुरक्षा घटनाओं को प्रबंधति कयिा, जिससे डेटा सुरक्षा को लेकर चतिाओं में वृद्धि हुई है।

## नविश गंतव्य के रूप में अपना आकरषण बढ़ाने के लयि भारत क्यिा कदम उठा सकता है?

- **अवसंरचना के वकिस में तवरण:** भारत को परयोजना कारयानवयन में तेजी लाकर और नविश बढ़ाकर अपनी अवसंरचना अंतराल को पाटने को प्रारथमकिता देनी चाहयि।
  - रसद दकषता में सुधार पर बल दयिा जाना चाहयि; भारत की रसद लागत (GDP का 14%) वकिसति देशों (8-10%) की तुलना में काफी अधिक है। पीएम गतिा शकतिा राष्टरीय मास्टर प्लान जैसी पहलों को तेजी से अगरेषति करना चाहयि।
  - सफल कारयानवयन से संभावति रूप से प्रतविरष रसद लागत में अरबों डॉलर की बचत हो सकती है तथा नरियात प्रतस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है।
- **वनियामक प्रकरयिाओं का धारारेखांकन:** भारत को अनुपालन भार को कम करने तथा व्यापार सुगमता के लयि अपने वनियामक वातावरण को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता है।
  - सरकार को 25,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त करने और छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने में अपनी सफलता को आगे बढ़ाना चाहयि।
  - सभी केंदरीय और राज्य स्तरीय अनुमोदनों के लयि एकल खडिकी मंजूरी प्रणाली कारयानवति करने से परयोजना में होने वाली देरी में काफी कमी आ सकती है।
  - उदाहरण के लयि, गुजरात की एकल खडिकी प्रणाली की सफलता को राष्टरीय स्तर पर कारयानवति कयिा जा सकता है।
  - वभिन्न वनियामक प्रकरयिाओं को डजिटिल बनाने और एकीकृत करने से व्यवसायों को प्रतविरष अनुपालन लागत में अरबों की बचत हो सकती है।
- **श्रम वधिा सुधार और कौशल वकिस:** श्रम बाज़ार में सुनमयता की वृद्धि के लयि चार नए श्रम संहतिाओं को शीघरता और प्रभावी ढंग से कारयानवति करना महत्त्वपूरण है।
  - इसके साथ ही, भारत को रोजगार संबंधी अंतर को दूर करने के लयि अपने कौशल वकिस पहलों में तेजी लानी चाहयि।

- सरकार को **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** के तहत कुशल लोगों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- उद्योग जगत के साथ सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिये, जैसे **कक्किलाउड प्रौद्योगिकियों में 100,000 डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिये गूगल और नैसकॉम के बीच हाल ही में हुई साझेदारी।**
- **बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढीकरण:** भारत को बैंक तुलन पत्र को परशोधित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकृत करने के अपने प्रयास जारी रखने चाहिये।
  - भारतीय नज्जी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्वामतित्व संबंधी दशिश-नरिदेशों पर RBI के आंतरकि कार्य समूह की सफारिशों को कार्यान्वति करने से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक नविश आकर्षति हो सकती है।
- **भूमि सुधार और डजिटिलीकरण:** भूमि अभलिखों के डजिटिलीकरण और भूमि अरजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थति करने सहति व्यापक भूमि सुधारों को कार्यान्वति करना महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकार को सभी राज्यों में **डजिटिल इंडिया भूमि अभलिख आधुनकिकरण कार्यक्रम** के अंतर्गत भूमि अभलिखों के डजिटिलीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
  - सफल कार्यान्वयन से भूमि संबंधी विवादों में 50% तक कमी आ सकती है तथा परयोजना कार्यान्वयन समय में भी उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- **बौद्धकि संपदा अधिकार संरक्षण का सुदृढीकरण:** भारत को नविशकों का वशिवास बढ़ाने के लिये अपनी बौद्धकि संपदा अधिकार व्यवस्था को सुदृढ बनाने पर ध्यान केंद्रति करना चाहिये, वशिष रूप से उच्च तकनीक और अनुसंधान एवं विकास-गहन क्षेत्रों में।
  - पेटेंट की आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिये, पहले चरण के लिये नरिधारति समय सीमा को घटाकर **4-15 महीने (वर्तमान में 18 महीने) कथि जा सकता है**, जसिसे यह अमेरिका और चीन के अनुरूप हो जाणा।
  - पेटेंट परीक्षकों की संख्या बढ़ाने और IP कार्यालयों का आधुनकिकरण करने से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मलि सकती है।
- **डजिटिल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा का संवर्द्धन:** भारत को अपने डजिटिल अवसंरचना विकास में तेज़ी लानी चाहिये, जसिका लक्ष्य **भारतनेट परयोजना** के तहत सभी गाँवों तक उच्च गति की इंटरनेट अभगिम्यता प्रदान करना है।
  - सरकार को औसत फकिस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कार्यनीति** को कार्यान्वति करने और एक सुदृढ प्रणाली स्थापति करने से साइबर सुरक्षा घटनाओं में **50% तक कमी आ सकती है** और भारत को डेटा-संचालति नविश के लिये एक सुरक्षति गंतव्य के रूप में स्थापति कथि जा सकता है।
- **सतत् विकास को प्रोत्साहन:** भारत को ई.एस.जी.-केंद्रति नविशों को आकर्षति करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् प्रथाओं की ओर अपने परिवर्तन में तेज़ी लानी चाहिये।
  - इसके अतरिकित, **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं और जल संरक्षण को बढ़ावा देने से** संसाधन की कमी की समस्या का समाधान हो सकता है।
  - ये उपाय संभावति रूप से वर्ष 2030 तक **100 बलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** हरति नविश आकर्षति कर सकते हैं तथा भारत को संवहनीय वनरिमाण में अग्रणी बना सकते हैं।
- **शकिषा और कौशल विकास को संवर्द्धन:** भारत को अपनी शकिषा प्रणाली को उद्योग जगत की ज़रतों, वशिषकरउभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रति करना चाहिये।
  - डजिटिल कौशल और व्यावहारकि प्रशकिषण पर ध्यान केंद्रति करते हुए **राष्ट्रीय शकिषा नीति 2020 को** प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना महत्त्वपूर्ण है।
  - भारतीय कौशल संस्थान जैसे सफल मॉडलों को अग्रषति करने से, जसिका उद्देश्य उद्योग-प्रासंगकि प्रशकिषण प्रदान करना है, कौशल अंतर को पाटने में सहायता मलि सकती है।

## नषिकरष:

वैश्वकि नविश केंद्र बनने की दशिश में भारत की यात्रा एक **आशाजनक पथ पर है**, जो सामरकि सुधारों, अवसंरचनात्मक विकास और एक युवा, तकनीक-परेमी कार्यबल द्वारा संचालति है। अपनी कषमता को पूरी तरह से साकार करने के लिये, भारत को अवसंरचना **नयामक जटलिता और कौशल विकास में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना चाहिये**, साथ ही अपनी **डजिटिल और सतत् विकास पहलों को सुदृढ करना चाहिये**। लक्षति उपायों के साथ, भारत वैश्वकि नविश के लिये एक शीर्ष गंतव्य के रूप में अपनी स्थति को सुदृढ कर सकता है।

????????????????????:

नविश गंतव्य आकर्षण के रूप में भारत के समकष बाधा प्रस्तुत करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा वदिशी और घरेलू नविश के लिये इसकी कषमता के संवर्द्धन हेतु कौन-से सामरकि उपाय अंगीकृत कथि जा सकते हैं? चर्चा कीजथि।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित् वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????

प्रश्न. भारत की वदिशी मुद्रा आरक्षति नधि में नमिनलखिति में से कौन-सा एक मदसमूह सम्मलिति है?

- वदिशी मुद्रा परसिम्पत्त, वशिष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) तथा वदिशों से ऋण
- वदिशी मुद्रा परसिम्पत्त, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वर्ण तथा वशिष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०)

- (c) वदिशी मुद्रा परसिम्पत्ता, वशि्व बैंक से ःरण तथा वशिष आहरण अधकिार (एस० डी० आर०)  
(d) वदिशी मुद्रा परसिम्पत्ता, भारतीय रज़िरव बैंक द्वारा धारति स्वरण तथा वशि्व बैंक से ःरण

उत्तर: (b)

**प्रश्न.** भारत में प्रत्यक्ष वदिशी नविश के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सी उसकी प्रमुख वशिषता मानी जाती है?

- (a) यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कम्पनी में पूँजीगत साधनों द्वारा कयिा जाने वाला नविश है ।  
(b) यह मुख्यतः ःरण सृजति न करने वाला पूँजी प्रवाह है ।  
(c) यह ऐसा नविश है जिससे ःरण-समाशोधन अपेक्षति होता है ।  
(d) यह वदिशी संस्थागत नविशकों द्वारा सरकारी प्रतभितियों में कयिा जाने वाला नविश है ।

उत्तर: (b)

**??????:**

**प्रश्न.** भारतीय अर्थव्यवस्था के वकिस में एफ.डी.आइ. की आवश्यकता की पुष्टि कीजयिे । हस्ताक्षरति समझौता-ज्जापनों तथा वास्तवकि एफ.डी.आइ. के बीच अंतर क्यो है? भारत में वास्तवकि एफ.डी.आइ. को बढ़ाने के लयि सुधारात्मक कदम सुझाइए । (2016)

**प्रश्न.** रक्षा क्षेत्रक में वदिशी प्रत्यक्ष नविश (एफ.डी.आइ.) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है । भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्य प्रभाव अपेक्षति हैं? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/india-s-rise-as-a-global-investment-hub>

